"हम अपने युवाओं की शिक्षा, उच्च शिक्षा, कौशलीकरण, पुन:कौशलीकरण और कौशल उन्नयन के लिए प्रधान मंत्री के विज़न को सकारात्मक करने हेतु शिक्षा मंत्रालय के साथ साझेदारी में काम करेंगे": श्री राजीव चंद्रशेखर, केंद्रीय राज्य मंत्री, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

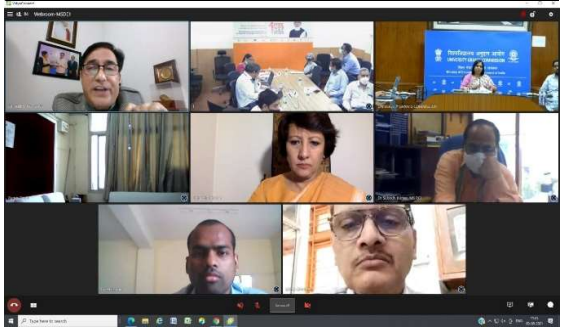

दिल्ली, 3 अगस्त 2021: आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की पहली वर्षगांठ पर, भारत की शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव की मैपिंग, **कौशल, उद्यमशीलता विकास और रोजगारपरक चुनौतियां और अवसर,** विषय पर कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा एक वेबिनार आयोजित किया गया। **माननीय राज्य मंत्री, श्री राजीव चंद्रशेखर, एमएसडीई** ने अपने सम्बोधन में कहा, "हम एनईपी 2020 का पहला वर्ष, कौशल विकास का पाँचवाँ वर्ष और स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहे हैं। जिस प्रकार हम स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाते हैं, उसी प्रकार हम, विशेष रूप से आज के बच्चे भी 25 वर्ष के बाद भावी भारत 2047 की ओर देखते हैं। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न के आधार पर, एनईपी बेहद परिवर्तनकारी है और व्यावसायिक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम एकीकरण से वर्तमान और भविष्य के छात्रों के लिए दो बहुत ही व्यवहार्य और आकर्षक आजीविका के रास्ते बनाता है। चूंकि स्कूली शिक्षा ज्ञान प्रदान करती है- उच्च शिक्षा और कौशलीकरण आजीविका के सूक्ष्म उद्यमशीलता और उद्यमशीलता, समृद्धि के दो मार्ग प्रदान करते हैं और बच्चों को लचीले जीवन और आजीविका विकल्पों को चुनने की अनुमति देते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "कौशल मंत्रालय ने अपने वर्तमान कार्यबल को सशक्त बनाने, और नवोन्मेष करने के लिए **प्रधान मंत्री** के आह्वान का पालन किया है। हम अपने युवाओं के लिए शिक्षा, उच्च शिक्षा, कौशलीकरण, पुन:कौशलीकरण और कौशल उन्नयन के प्रधान मंत्री के विजन साकार करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर काम करेंगे। देश के युवाओं को, हमारी पीढ़ी ने उपहार स्वरूप, भारत स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहा है।"

व्यावसायिक शिक्षा को आकांक्षी बनाने के उद्देश्य से एमएसडीई की कौशल और उद्यमशीलता पहल के साथ एनईपी 2020 के संरेखण पर चर्चा हुई। एमएसडीई युवाओं की रोजगारपरकता की सुविधा देने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है और उन्हें बाजार संचालित रोजगार विकल्प लेने के लिए तैयार करना चाहता है। इस दिशा में मंत्रालय कौशल विकास और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए अल्पावधि और दीर्घावधि कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से एक आवश्यक इकोसिस्टम बनाने के लिए विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों को लागू कर रहा है।

श्री रवि मित्तल, सचिव, एमएसडीई ने अपने स्वागत भाषण में कहा, "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कार्यान्वयन व्यावसायिक और औपचारिक शिक्षा को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण है और यह नीति अपना पहला वर्ष पूरा होने के पहले से ही बहुत उपयोगी साबित हुई है, जो हमें स्थिर सुधारों को लागू करने के लिए एक रोडमैप प्रदान करती है। जैसे-जैसे हम इस विजन डॉक्युमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मेरा मानना है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में और अधिक मूलभूत सुधार होंगे।

कौशल विकास और उद्यमशीलता की नीतियां भारत की अनूठी जनसांख्यिकीय रूपरेखा और कार्यबल की प्रकृति के संदर्भ में विकसित की गई हैं। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी का घर है, जिसमें भारत की 50% से अधिक आबादी 25 वर्ष से कम आयुवर्ग की है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2030 तक, देश में दुनिया का सबसे अधिक युवा और सबसे बड़ा कार्यबल होगा, जो एक अरब से अधिक होगा। लगभग 80% कार्यबल अनौपचारिक रूप से नियोजित होने के साथ, लक्षित कौशलीकरण और रोजगार सृजन पहल के माध्यम से रोजगार के अवसरों में सुधार करना महत्वपूर्ण है।

इस अवसर पर श्री राज नेहरू, कुलपति, विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय, हरियाणा सरकार; डॉ. निर्मलजीत सिंह कलसी, अध्यक्ष, एनसीवीईटी; श्री मनोज आहूजा, अध्यक्ष, सीबीएसई; सुश्री जाह्नबी फूकन, पूर्वोत्तर में उद्यमशीलता पक्ष-पोषण में शामिल और सुश्री अनुराधा वेमुरी, संयुक्त सचिव, एमएसडीई. सहित ख्यात वक्ताओं की गरिमामयी उपस्थित थी।